Machine Translated by Google

पाकिस्तान जा रहा चीनी 'परमाणु' माल जब्त किया गया

Karachi-bound 'dual-use' consignment was intercepted on January 22 in Mumbai; machines in it could be used in nuclear weapons programme

यह खेप मुंबई में जब्त की गई। विशेष व्यवस्था - Photo:

DINAKAR PERI
नई दिल्ली

नवीनतम खोज में चीन से दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के संभावित हस्तांतरण की संभावना है जिनका उपयोग किया जा सकता है
पाकिस्तान का परमाणु हथियार कार्यक्रम, दो उन्नत कंप्यूटर संख्यात्मक नियंत्रण (सीएनसी)
जीकेडी, इटली द्वारा निर्मित और कराची बंदरगाह के लिए जा रही मशीनें भारतीयों द्वारा जब्त कर ली गईं
जनवरी में मुंबई बंदरगाह पर सीमा शुल्क। के अनुसार, वे अभी भी भारतीय हिरासत में हैं
सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्र।

यह खेप 9 जनवरी को चीन के शेकोउ बंदरगाह से एक व्यापारी जहाज पर भेजी गई थी, और कॉसमॉस इंजीनियरिंग के साथ सीएमए सीजीएम अट्टिला , एक माल्टा-ध्वजांकित
कराची बंदरगाह की ओर जा रही थी।
एक सूत्र ने कहा, कंसाइनी होने के नाते। "जहाज न्हावा शेवा पोर्ट (जेएनपीटी) मुंबई पहुंचा
22 जनवरी, 2024 को भारतीय सीमा शुल्क अधिकारियों ने खेप को जब्त कर लिया
पाकिस्तान और चीन द्वारा संभावित प्रसार चिंताओं पर खुफिया जानकारी, "सूत्र ने कहा।
उपकरण का उपयोग पाकिस्तान के मिसाइल विकास के लिए महत्वपूर्ण भागों के निर्माण में किया जा सकता है
कार्यक्रम, एक अन्य सूत्र ने कहा।

CONTINUED ON ❯ PAGE 8

Machine Translated by Google

कर्नाटक विस्फोट: पुलिस जांच के तार 2022 कुकर विस्फोट मामले से जुड़े हैं

संदिग्ध का एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गया है. विशेष व्यवस्था Photo:

THE HINDU BUREAU
बेंगलुरु

शुक्रवार को व्हाइटफील्ड के पास बेंगलुरु के टेक कॉरिडोर में रामेश्वरम कैफे में हुए आईईडी विस्फोट की जांच कर रही बेंगलुरु सिटी पुलिस अब 2022 के मंगलुरु कुकर विस्फोट मामले से इसके संभावित लिंक की तलाश कर रही है।

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शनिवार को कहा कि जांच से संकेत मिला है कि दोनों जुड़े हो सकते हैं, और जिन्होंने 2022 मामले की जांच की थी वे अब वर्तमान जांच में शामिल हो गए हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि दोनों विस्फोटों में इस्तेमाल किया गया डेटोनेटर और टाइमर एक जैसे और कम तीव्रता के थे।

शिवमोग्गा जिले में एक आतंकी साजिश मामले में फरार आरोपी मोहम्मद शारिक 19 नवंबर, 2022 को कुकर बम के साथ आया था, जो मंगलुरु के बाहरी इलाके में एक ऑटोरिक्शा में गलती से फट गया था। तब एक जांच में कोयंबटूर कार विस्फोट मामले के कुछ लिंक का संकेत मिला था, जो मंगलुरु घटना से कुछ हफ्ते पहले हुआ था। दोनों मामलों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के आरोपपत्रों में आरोप लगाया गया कि आरोपी इस्लामिक स्टेट से प्रेरित थे।

खुद को 'इस्लामिक रेजिस्टेंस काउंसिल' कहने वाले एक अज्ञात संगठन ने मंगलुरु विस्फोट की जिम्मेदारी ली थी। हालाँकि, सुरक्षा एजेंसियों को ऐसे किसी संगठन के अस्तित्व पर संदेह है।

जबकि सुरक्षा एजेंसियां अब मामलों के बीच संबंध की संभावना की जांच कर रही हैं, एक वरिष्ठ अधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि हालांकि जांच "इन पंक्तियों के बीच कई अन्य कोणों पर की जा रही है", वे "निर्णायक रूप से यह नहीं कह सकते कि दो विस्फोट हुए हैं" निश्चित रूप से जुड़ा हुआ है।"

बेंगलुरु पुलिस रेस्तरां के सीसीटीवी फुटेज से हमलावर के चेहरे की आंशिक छवि प्राप्त करने में सक्षम रही है। हालांकि आरोपी ने सफेद टोपी और काला फेस मास्क पहना हुआ है, लेकिन उसे रेस्तरां की सड़क पर और उसके अंदर भी देखा जा सकता है।

Machine Translated by Google

चुनाव आयोग ने पक्षपात करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आह्वान किया

कड़ी निगरानी: शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार व अन्य. संदीप सक्सेना - Photo:

PRESS TRUST OF INDIA
लखनऊ

चुनाव आयोग (ईसी) ने शनिवार को सभी जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधीक्षकों को उन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जो पक्षपात में लिप्त हैं।

चुनाव आयोग का यह कदम "प्रलोभन-मुक्त" लोकसभा चुनाव सुनिश्चित करने और सभी पार्टियों को समान अवसर प्रदान करने के लिए उठाया गया है।

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने और पक्षपात करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए सभी जिला मजिस्ट्रेटों और एसपी को निर्देश जारी किए गए हैं।

“समान अवसर के लिए अत्याधुनिक स्तर पर काम करने वाले कनिष्ठ अधिकारियों के साथ निष्पक्षता सुनिश्चित करें। सभी डीईओ (जिला चुनाव अधिकारियों) को राजनीतिक दलों द्वारा दर्ज की गई शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा गया है, ”श्री कुमार ने प्रेसपर्सन को बताया।

उन्होंने कहा, ''वर्तमान में कोई भी शिकायत लंबित नहीं है और सभी समस्याओं का संतोषजनक समाधान कर दिया गया है।''

श्री कुमार, जिनके साथ चुनाव आयुक्त अरुण गोयल भी थे, ने अधिकारियों से प्रतिरूपण के मामलों की जाँच करने को भी कहा।

Fraudulent activities

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि जो लोग चुनाव प्रक्रिया से संबंधित फर्जी गतिविधियों में शामिल हैं, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि फर्जी खबरों से निपटने के लिए जिला स्तर पर एक सोशल मीडिया सेल बनाया जाना चाहिए ताकि "झूठी खबरों से तुरंत निपटा जा सके"।

श्री कुमार लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य की राजधानी के तीन दिवसीय दौरे पर थे।

Machine Translated by Google

IAF ने LAC के पास लैंडिंग स्ट्रिप की ब्लैक-टॉपिंग का काम पूरा किया

DINAKAR PERI
नई दिल्ली

पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के करीब न्योमा में भारतीय वायु सेना के एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड (ALG) को अब ब्लैक-टॉप (पक्का रनवे) कर दिया गया है, जबकि रनवे का विस्तार करने के लिए काम चल रहा है ताकि यह सूत्रों के अनुसार, अंततः लड़ाकू विमानों को संभाल सकता है।

“काम लगभग 15% पूरा हो चुका है और अब सर्दी के कारण रुका हुआ है। यह अप्रैल में दोबारा शुरू होगा. यह दो साल में पूरा होने की राह पर है।” इस आशंका पर प्रतिक्रिया देते हुए कि हवाई क्षेत्र चीन के लिए एक आसान लक्ष्य बन सकता है क्योंकि यह एलएसी से केवल 30 किमी दूर है, सूत्र ने कहा कि यह बहुत अच्छी तरह से स्थित है और भारत के लिए एक बड़ा फायदा साबित होगा। न्योमा एएलजी पर फिक्स्ड-विंग विमान की पहली लैंडिंग 18 सितंबर 2009 को हुई थी, जब एक एएन-32 परिवहन विमान वहां उतरा था। रनवे को अब 9,000 या 10,000 फीट तक बढ़ाया जा रहा है ताकि यह भारतीय वायुसेना की सूची में सभी लड़ाकू विमानों को संभालने में सक्षम हो सके।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले सितंबर में एएलजी की आधारशिला रखी थी और विश्वास जताया था कि यह हवाई क्षेत्र सशस्त्र बलों के लिए "गेम-चेंजर" साबित होगा। एएलजी के विकास की लागत लगभग ₹200 करोड़ है।

Strategic infrastructure

भारतीय वायुसेना के पास लेह, थोइस और कारगिल में हवाई क्षेत्र हैं, साथ ही डौलेट बेग-ओल्डी और फुकचे में एएलजी भी हैं। हालाँकि, लेह और थोइस हवाई क्षेत्र आंतरिक क्षेत्रों में स्थित हैं और अधिकारियों ने कहा कि न्योमा का मौसम अन्य दो हवाई क्षेत्रों की तुलना में बहुत अधिक स्थिर है।

2020 में चीनी सेना के साथ गतिरोध के चरम पर, IAF ने सैनिकों की आगे की तैनाती का समर्थन करने के लिए अपने Mi-17 मध्यम-लिफ्ट हेलीकॉप्टर, CH-47F चिनूक हेवी-लिफ्ट हेलीकॉप्टर, और AH-64E अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को न्योमा में स्थानांतरित कर दिया। साथ ही निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने के उद्देश्यों के लिए भी।

जैसा कि बताया गया हिंदू इससे पहले, उच्च ऊंचाई वाले हवाई क्षेत्रों में लड़ाकू विमानों का सामना करने वाली चुनौतियों पर काबू पाने के लिए है, इंजनों में बदलाव किया जा रहा है ताकि उन्हें कम तापमान पर शुरू करने में सक्षम बनाया जा सके।

Machine Translated by Google

सीजेआई ने जमानत देने के लिए ट्रायल जजों की 'बढ़ती अनिच्छा' को चिह्नित किया

Worried about the increasing number of bail appeals reaching the High Courts and the Supreme Court, Chief Justice says the long-standing principle of 'bail being the rule' seems to losing ground

हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह के साथ सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़। पीटीआई - Photo:

THE HINDU BUREAU
नई दिल्ली

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को इस बढ़ती आशंका को रेखांकित किया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार निचली अदालतों में कमजोर हो रहा है, क्योंकि जेल, जमानत नहीं, नियम बन गया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जमानत देने को लेकर ट्रायल न्यायाधीशों की ओर से "अनिच्छा बढ़ रही है"।

यह उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय तक पहुँचने वाली जमानत अपीलों की बढ़ती संख्या से स्पष्ट था। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने अखिल भारतीय जिला न्यायाधीशों के सम्मेलन में अपने संबोधन में कहा, "लंबे समय से चला आ रहा सिद्धांत कि 'जमानत नियम है, जेल अपवाद है' अपनी जमीन खोता नजर आ रहा है... इस प्रवृत्ति के लिए गहन पुनर्मूल्यांकन की जरूरत है।" गुजरात में कच्छ.

मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी तब आई जब जमानत देने पर सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड असमान रहा है। छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद ने कई स्थगनों के बाद अपनी जमानत याचिका वापस लेने का फैसला किया। कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया की जमानत खारिज कर दी थी.

'Adjournment culture'

मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने अदालतों में "स्थगन संस्कृति" पर भी प्रकाश डाला। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि स्थगन, जो कभी भी सामान्य होने का इरादा नहीं था, न्यायिक प्रक्रिया के भीतर सामान्य हो गया है।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "स्थगन की यह संस्कृति किसी मामले में समय को प्रभावी ढंग से निलंबित कर सकती है, जिससे वादियों की पीड़ा बढ़ सकती है और बैकलॉग का चक्र कायम रह सकता है।"

देरी इतनी होती है कि संपत्ति विवाद में फंसा किसान शायद अपने जीवनकाल में इसका परिणाम कभी नहीं देख पाता। “हमें अपने नागरिकों के मामले का फैसला अदालत द्वारा किए जाने के लिए उनके मरने का इंतजार नहीं करना चाहिए। यौन उत्पीड़न की एक पीड़िता की कल्पना करें जिसका मामला कई वर्षों तक अदालतों में अनसुलझा पड़ा है। क्या यह न्याय तक पहुँचने के उनके मौलिक अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन नहीं है?” उसने पूछा।

मुख्य न्यायाधीश ने जिला न्यायपालिका को लिंग-रूढ़िवादी भाषा का उपयोग करने के खिलाफ सलाह दी जो प्रणालीगत असमानताओं को बनाए रखने और कानूनी प्रणाली के भीतर महिलाओं को हाशिए पर धकेलने में योगदान करती है।

मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि अब जिला न्यायपालिका की कामकाजी ताकत में महिलाएं 36.3% हैं, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों के लिए रिक्ति दर "चौंकाने वाली" है, जो कुल रिक्त पदों का 66.3% है।

Machine Translated by Google

संघ सरकार द्वारा पत्रिकाओं का पंजीकरण ऑनलाइन हो गया है। नए अधिनियम को अधिसूचित करता है

THE HINDU BUREAU
नई दिल्ली

नया प्रेस और पत्रिकाओं का पंजीकरण (पीआरपी) अधिनियम, 2023 लागू हो गया है और पुराना प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम, 1867 अब निरस्त हो गया है।

केंद्र ने नए कानून और संबंधित नियमों को अपने आधिकारिक गजट में अधिसूचित कर दिया है। तदनुसार, अधिनियम 1 मार्च से प्रभावी है। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का पंजीकरण प्रेस सेवा पोर्टल में ऑनलाइन हो गया है, जबकि भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार (आरएनआई) का नाम बदलकर प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (पीआरजीआई) कर दिया गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने शनिवार को...

“डिजिटल इंडिया के लोकाचार के अनुरूप, नया अधिनियम देश में समाचार पत्रों और अन्य पत्रिकाओं के पंजीकरण की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली प्रदान करता है। नई प्रणाली मौजूदा मैनुअल, बोझिल प्रक्रियाओं को प्रतिस्थापित करती है जिसमें कई चरणों और विभिन्न चरणों में अनुमोदन शामिल होते हैं जो प्रकाशकों के लिए अनावश्यक कठिनाइयों का कारण बन रहे थे, ”यह कहा। इससे पहले, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रेस सेवा पोर्टल लॉन्च किया था, जिसके माध्यम से नए अधिनियम द्वारा अनिवार्य विभिन्न आवेदन ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं।

प्रेस सेवा पोर्टल कागज रहित प्रसंस्करण सुनिश्चित करता है और ई-साइन सुविधा, डिजिटल भुगतान गेटवे, तत्काल डाउनलोड के लिए क्यूआर कोड-आधारित डिजिटल प्रमाणपत्र, प्रिंटिंग प्रेस द्वारा सूचना प्रदान करने के लिए ऑनलाइन प्रणाली, शीर्षक उपलब्धता के लिए संभावना का प्रतिशत, ऑनलाइन पहुंच के साथ सेवाएं प्रदान करता है। सभी प्रकाशकों के लिए पंजीकरण डेटा, वार्षिक विवरण दाखिल करना, आदि। इसका इरादा एक चैटबॉट-आधारित इंटरैक्टिव शिकायत समाधान तंत्र स्थापित करने का भी है, ”मंत्रालय ने कहा।

पोर्टल के साथ सभी संबंधित जानकारी और उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस के साथ एक नई वेबसाइट भी है। नया अधिनियम पुराने कानून द्वारा आवश्यक पंजीकरण के दायरे से पुस्तकों और पत्रिकाओं को हटा देता है। यह एक आवधिक को परिभाषित करता है "एक समाचार पत्र सहित कोई भी प्रकाशन जो नियमित अंतराल पर प्रकाशित और मुद्रित होता है जिसमें सार्वजनिक समाचार या सार्वजनिक समाचार पर टिप्पणियाँ शामिल होती हैं लेकिन इसमें वैज्ञानिक, तकनीकी और शैक्षणिक प्रकृति की कोई पुस्तक या पत्रिका शामिल नहीं होती है"।

इसलिए, "पुस्तक, या वैज्ञानिक, तकनीकी और शैक्षणिक प्रकृति की पुस्तक या जर्नल सहित" को पीआरजीआई के साथ पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।

Machine Translated by Google

केंद्र, टीआईपीआरए मोथा, त्रिपुरा सरकार। त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करें

As part of the deal, a committee would be formed to resolve issues of the indigenous people of Tripura, who make up 33% of State's population

शनिवार को नई दिल्ली में समझौते पर हस्ताक्षर के दौरान माणिक साहा, प्रद्योत देबबर्मा और अन्य के साथ अमित शाह। पीटीआई - Photo: - Photo:

SYED SAJJAD ALI
अगरतला

भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और टिपराहा स्वदेशी प्रगतिशील क्षेत्रीय गठबंधन (टीआईपीआरए) ने त्रिपुरा के स्वदेशी लोगों, जो आबादी का 33% हिस्सा हैं, के सामने आने वाले मुद्दों के समाधान के लिए शनिवार को एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए।

समझौते में राज्य के स्वदेशी लोगों के "इतिहास, भूमि अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक विकास, पहचान, संस्कृति और भाषा" से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए एक संयुक्त कार्य समिति का गठन शामिल है।
टीआईपीआरए, जिसे टीआईपीआरए मोथा के नाम से भी जाना जाता है, समय पर समाधान निकलने तक किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शन से दूर रहने पर सहमत हुआ है।

समझौते पर टीआईपीआरए के संस्थापक और शाही वंशज प्रद्योत बिक्रम माणिक्य देब बर्मा, पार्टी अध्यक्ष बिजॉय कुमार ह्रांगखॉल और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता अनिमेष देबबर्मा ने अपनी पार्टी की ओर से हस्ताक्षर किए। मुख्य सचिव जेके सिन्हा और गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव (एनई) पीयूष गोयल ने समझौते में क्रमशः त्रिपुरा सरकार और केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व किया। हस्ताक्षर कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा और उनके मंत्रिमंडल के दो आदिवासी मंत्री - विकास देबबर्मा और सुक्ला चरण नोआतिया उपस्थित थे।

शनिवार को हस्ताक्षरित समझौते में संयुक्त कार्य समिति के गठन के लिए कोई समयसीमा निर्दिष्ट नहीं की गई, लेकिन टीआईपीआरए के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि संयुक्त कार्य समिति का गठन अगले सप्ताह किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि समिति में मंत्रालय, त्रिपुरा सरकार, टीआईपीआरए और इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आईपीएफटी) के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो सत्तारूढ़ गठबंधन में भाजपा का गठबंधन सहयोगी है।

समझौते पर हस्ताक्षर के बाद कई जगहों पर जश्न मनाया गया।

समझौते पर हस्ताक्षर श्री प्रद्योत माणिक्य द्वारा स्वदेशी लोगों की समस्याओं का संवैधानिक समाधान प्रदान करने में केंद्र सरकार की कथित अनिच्छा के विरोध में पश्चिम त्रिपुरा के हताई कोटर (पूर्व में बोरोमुरा हिल्स) में आमरण अनशन शुरू करने के तीन दिन बाद हुआ।

अपना विरोध शुरू करने के एक घंटे के भीतर, उन्होंने घोषणा की कि उन्हें मंत्रालय से फोन आया है और वे कार्यक्रम स्थल से दिल्ली के लिए रवाना हो गए।

टीआईपीआरए ग्रेटर टिपरालैंड या स्वदेशी आबादी के लिए एक अलग राज्य की मांग के साथ राज्य की राजनीति में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया है।

त्रिपक्षीय समझौते के जवाब में, सीपीआई (एम) नेता और राज्य विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष पबित्रा कर ने कहा कि यह प्रकरण आगामी चुनाव को ध्यान में रखकर रचा गया था।

Machine Translated by Google

'सीएए आंदोलन के बाद यूपी में कमिश्नरी सिस्टम को मंजूरी'

ओपी सिंह

VIJAITA SINGH
नई दिल्ली

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के दो शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली को मंजूरी दे दी है
और नोएडा, नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के पारित होने के खिलाफ राज्य में विरोध प्रदर्शन शुरू होने के कुछ दिनों बाद
2019 में, राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह द्वारा लिखी गई एक नई किताब में कहा गया है।

श्री सिंह ने 1 जनवरी, 2018 से 30 जनवरी, 2020 तक उत्तर प्रदेश पुलिस का नेतृत्व किया। इसमें 22 लोग मारे गए थे
9 दिसंबर, 2019 को संसद द्वारा सीएए पारित होने के बाद उत्तर प्रदेश में 83 लोग
सीएए और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में मारे गए।

सीएए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और छह गैर-मुस्लिम समुदायों को "अप्रलेखित" नागरिकता की अनुमति देता है
बांग्लादेश जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुका है। ऐसी आशंकाएं और आशंकाएं हैं कि अधिनियम,
जिसे अभी तक लागू नहीं किया गया है, इससे नागरिक रजिस्टर से बाहर किए गए गैर-मुसलमानों, जबकि बाहर रखे गए मुसलमानों को लाभ होगा
साबित करनी होगी अपनी नागरिकता सरकार ने पहले संसद को सूचित किया था कि “अब तक सरकार
राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी तैयार करने का कोई निर्णय नहीं लिया है।

“सीएए के बाद के विरोध प्रदर्शनों ने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ आमने-सामने बातचीत के लिए माहौल तैयार किया। पुलिस के पास कोई मजिस्ट्रियल नहीं था
शक्तियां अभी तक... लगभग 4 मिलियन की आबादी वाले लखनऊ जैसे शहर को आयुक्तालय की आवश्यकता थी,'' वह लिखते हैं
किताब अपराध, गंदगी और गम्प्शन, केस फ़ाइलें का एक आईपीएस अफ़सर .

किताब में कहा गया है कि लखनऊ में सीएए विरोधी प्रदर्शन शुरू होने के बाद सीएम ने उनसे पूछा था कि इसकी पुनरावृत्ति कैसे हो सकती है
रोका जाए.

“सर, अगर कमिश्नरी प्रणाली लागू होती, तो हम आंदोलन को कहीं अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर पाते
और अच्छे समय में. हमें एक तेज़ तंत्र की आवश्यकता है जो पुलिस को त्वरित समय में प्रतिक्रिया देने की अनुमति दे,'' उन्होंने श्री को सूचित किया।
आदित्यनाथ. सीएम ने कहा कि वह प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करने के लिए तैयार हैं और कागजी कार्रवाई में तेजी लाने को कहा।

13 जनवरी, 2020 को राज्य कैबिनेट द्वारा लखनऊ और नोएडा के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। व्यवस्था देती है
शक्तियाँ आमतौर पर जिला मजिस्ट्रेटों को सौंपी जाती हैं, जैसे कि कर्फ्यू लगाना और आग का उपयोग, पुलिस को।

Machine Translated by Google

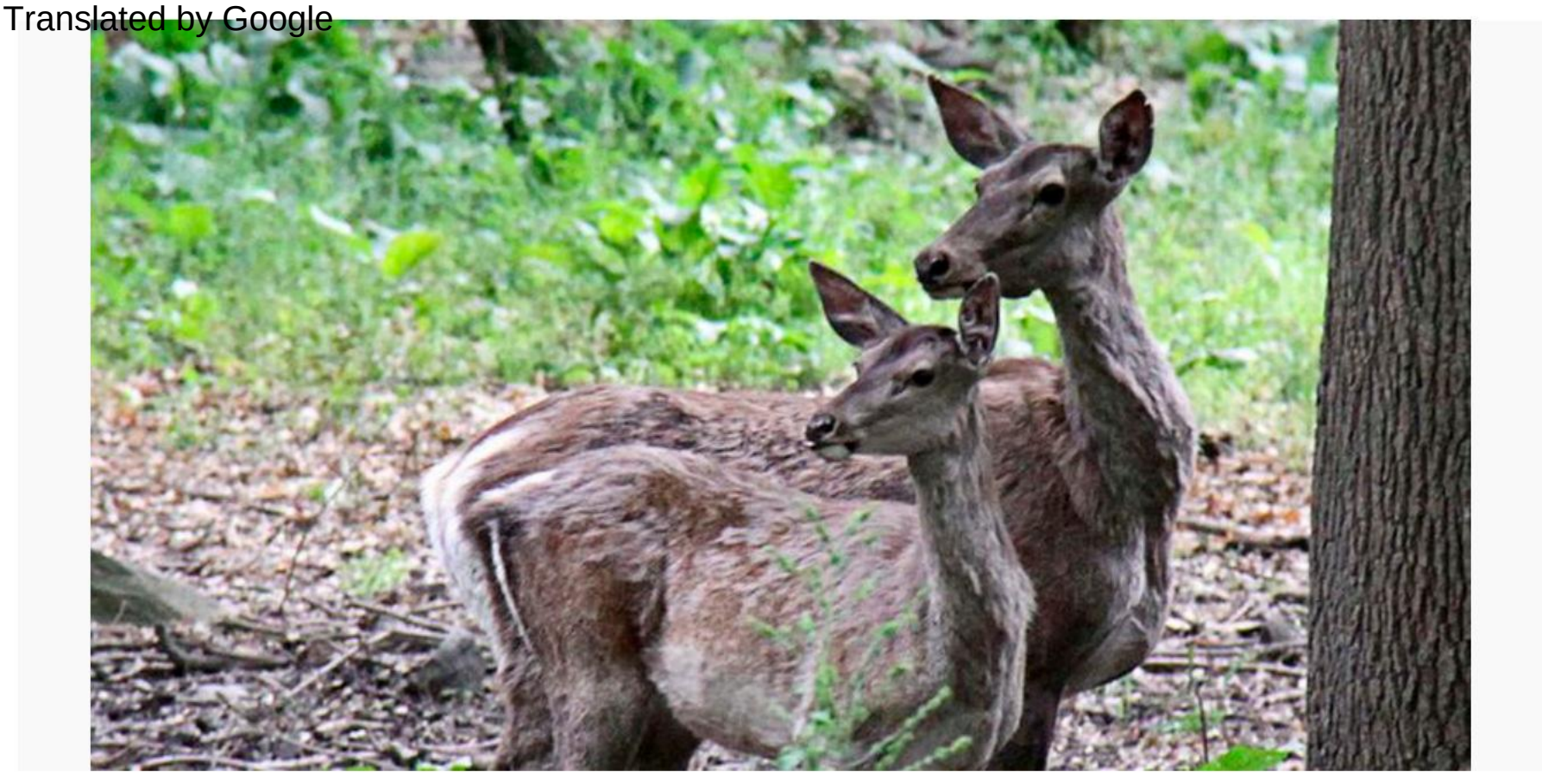

मेटिंग कॉल से संकेत मिलता है कि लुप्तप्राय हंगुल वापसी की राह पर हैं

बढ़ती संख्या: श्रीनगर के बाहरी इलाके दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में कश्मीरी हंगुल का एक जोड़ा देखा गया। फाइल फोटो - Photo:

PEERZADA ASHIQ
SRINAGAR

कश्मीर का अत्यधिक शर्मीला और संवेदनशील जानवर, हंगुल, जिसे हिरण की गंभीर रूप से लुप्तप्राय स्वदेशी प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, ने पिछले शरद ऋतु में सबसे स्वस्थ रूटिंग या संभोग मौसमों में से एक की सूचना दी है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि रूटिंग के दौरान हंगुल की दहाड़ या आवाज़ से संकेत मिलता है कि इस वसंत में उनकी संख्या 300 से अधिक हो जाएगी, तीन दशकों से अधिक समय में पहली बार।

“पिछले साल अक्टूबर में रूटिंग सीज़न के दौरान वन्यजीव कर्मचारियों द्वारा रिकॉर्ड की गई कॉल पिछले वर्षों की तुलना में स्वस्थ थीं। वास्तव में, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, जो हंगुल का घर है, 25 सितंबर से 18 अक्टूबर के बीच आगंतुकों के लिए बंद कर दिया गया था ताकि वे निर्बाध रूप से घूम सकें,'' रशीद नकाश, क्षेत्रीय वन्यजीव वार्डन, कश्मीर, ने बताया हिंदू .

1947 के बाद से, हंगुल, जो जम्मू-कश्मीर का राज्य पशु है, की आबादी में भारी गिरावट देखी गई। 1947 में, लगभग 2,000 देखे गए और 1968 तक यह संख्या गिरकर 384 हो गई।

वन्यजीव विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 2004 में हंगुल की आबादी मात्र 197 आंकी गई थी, जो 2015 में सबसे कम 183 हो गई और 2021 में लगातार वृद्धि के साथ 261 हो गई।

“वन क्षेत्रों पर तनाव और मानव हस्तक्षेप सहित कई गड़बड़ियों ने हंगुल के आवास को परेशान किया।
हालाँकि, अब हम बेहतर वातावरण प्रदान करने में सक्षम हैं। हम सभी गलियारों को सुरक्षित करने की योजना बना रहे हैं, विशेषकर उत्तर में वांगथ-नारानाग गलियारे को। हम यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र लेकर आ रहे हैं कि यातायात को नियंत्रित करके हंगुल के समूह गांदरबल में राजमार्गों पर सुरक्षित रूप से चलें,'' श्री नक़श ने कहा।

आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि प्रति 100 महिलाओं पर 19.2 पुरुष हैं "जो प्रति 100 महिलाओं पर 40-50 पुरुषों के आदर्श अनुपात से बहुत कम है"।

शेर-ए-कश्मीर कृषि और विज्ञान प्रौद्योगिकी-कश्मीर में वन्यजीव विज्ञान संकाय वानिकी के प्रमुख डॉ. खुर्शीद अहमद ने हंगुल के सामने आने वाले कुछ खतरों की पहचान की है।

“आस-पास के क्षेत्र में पानी की अनुपलब्धता ने हंगुल, विशेष रूप से गर्मियों में स्तनपान कराने वाली महिलाओं को, दाचीगाम के अंदर और बाहर अशांत आवासों की ओर जाने के लिए मजबूर किया होगा। यह हिरण के बच्चे के शिकारियों या यहां तक कि भेड़ के कुत्तों का शिकार बनने के कारकों में से एक के रूप में भी काम कर सकता है, ”श्री अहमद ने कहा।
जम्मू-कश्मीर वन्यजीव विभाग ने "जीविका सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा तंत्र प्रदान करने के लिए" 10 हंगुल स्थलों की पहचान की है।

शिकारगाह त्राल में लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए एक बंदी-प्रजनन सुविधा स्थापित की गई है।

Machine Translated by Google

शिकारी मछलियाँ हमलों के समन्वय के लिए तेजी से रंग परिवर्तन का उपयोग करती हैं

THE HINDU BUREAU

धारीदार मार्लिन ग्रह पर सबसे तेज़ जानवरों में से कुछ हैं और समुद्र के शीर्ष शिकारियों में से एक हैं।
समूहों में शिकार करते समय, व्यक्तिगत मार्लिन बारी-बारी से शिकार मछलियों के समूहों पर हमला करेगा। अब नए अध्ययन () में बताया गया है कि वे एक-दूसरे को घायल करने से बचने के लिए अपने शिकार पर हमले की इस बारी-बारी शैली का समन्वय कैसे कर सकते हैं। मुख्य बात तेजी से रंग बदलना है।

मार्लिन के समूहों द्वारा सार्डिन के समूहों के तेजी से रंग बदलने के तरीके का अध्ययन करते हुए, लेखकों ने पाया कि हमलावर मार्लिन 'ज्वलंत' हो गया और दूसरों की तुलना में कहीं अधिक चमकीला हो गया क्योंकि उसने अपना हमला किया और रंग तेजी से अपने 'गैर-उज्ज्वल' रंग में लौट आया। हमले के बाद. शोधकर्ताओं ने इस घटना का अध्ययन करने के लिए ड्रोन का उपयोग किया।

Reliable signal

वीडियो फ़ुटेज से पता चला कि जब मछली हमले के लिए आगे बढ़ती है तो अलग-अलग मार्लिन पर धारियाँ बहुत अधिक चमकीली हो जाती हैं, और जब वे तैरकर दूर चली जाती हैं तो वे धुंधली हो जाती हैं।

यह पता लगाने के लिए कि क्या बदलते रंग एक-दूसरे के साथ संवाद कर सकते हैं, उन्होंने 12 उच्च-रिज़ॉल्यूशन वीडियो क्लिप का विश्लेषण किया, जिनमें से प्रत्येक में दो अलग-अलग मार्लिन द्वारा सार्डिन के एक स्कूल पर दो अलग-अलग हमले शामिल थे।

उन्होंने बेतरतीब ढंग से चुने गए मार्लिन की तुलना में दो हमलावर मार्लिन पर धारियों के अंतर को भी निर्धारित किया जो हमला नहीं कर रहा था।

उनका विश्लेषण इस बात की पुष्टि करता है कि शिकारी मछलियाँ तेजी से रंग बदलती हैं, जिससे पता चलता है कि रंग परिवर्तन किसी व्यक्ति के हमले के लिए प्रेरित होने के विश्वसनीय संकेत के रूप में काम कर सकता है।

Dual purpose

हम्बोल्ट विश्वविद्यालय, बर्लिन, जर्मनी की डॉ. एलिसिया बर्न्स और पेपर के संबंधित लेखक ने एक विज्ञप्ति में कहा, "शिकारियों में रंग परिवर्तन दुर्लभ है, लेकिन विशेष रूप से समूह-शिकार करने वाले शिकारियों में।" "हालांकि यह ज्ञात है कि मार्लिन रंग बदल सकता है, यह पहली बार है कि इसे शिकार या किसी सामाजिक व्यवहार से जोड़ा गया है।"

खोज से पता चलता है कि मार्लिंस के पास संदेह से कहीं अधिक जटिल संचार चैनल हैं। शोधकर्ताओं का प्रस्ताव है कि रंग परिवर्तन उनके शिकार को भ्रमित करने के दोहरे उद्देश्य को भी पूरा कर सकता है।

अब वे अन्य प्रश्नों के साथ-साथ इस विचार का भी पता लगाने की उम्मीद करते हैं।

उदाहरण के लिए, वे यह पता लगाना चाहते हैं कि क्या मार्लिन अपनी रंग बदलने की क्षमताओं का उपयोग अन्य संदर्भों में करते हैं। लेखक यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या अकेले शिकार करते समय भी वे अपना रंग बदलते हैं और यह परिवर्तन उनके शिकार को कैसे प्रभावित करते हैं।

वे मछलियों की अन्य शिकारी प्रजातियों में भी इसी तरह के रंग परिवर्तन पर गौर कर रहे हैं।

Machine Translated by Google

Towards increased birth spacing

Short birth spacing — less than 18 months between two pregnancies — accounts for 31% of high-risk pregnancies

- A gap of two-three years between pregnancies is recommended to give a woman enough time to recover, regain her health, strength, and nourishment
- Currently condoms, combined oral contraceptive pills, emergency contraceptive pills, intrauterine contraceptive device, injectable contraceptive, and contraceptive tablet centchroman are offered to women
- The most common modern methods still used in India are female sterilisation (which is permanent) and male condoms
- Two new methods — a subdermal contraceptive implant, and the subcutaneous injectable contraceptive (DMPA-SC) — have been introduced in the public health programmes of a few States
- The two new methods can prevent pregnancy for three years (subcutaneous implants) and three-four months (DMPA-SC)

Many choices: The Indian family planning programme has for many years been offering a basket of contraception choices

- But there is lack of information and understanding among the end users, and there is limited engagement with communities
- Women do not feel comfortable and empowered to make their choices. Also, misconceptions, negative experiences, misinformation, and taboos, often fuel hesitancy

जीवनरक्षक आधुनिक गर्भनिरोधक का मामला

Evidence suggests that the most common modern methods still in use in the country are female sterilisation, which is permanent, or male condoms, which are often incorrectly used thereby reducing their effectiveness

JAYDEEP TANK

उच्च जोखिम वाली गर्भधारण पर लेख प्रसूति और स्त्री रोग समुदाय हिंदू 17 फरवरी को बड़ी चतुराई से एक महान मामले की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया
के लिए चिंता का विषय है, लेकिन अक्सर देश के बाकी हिस्सों द्वारा इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। भारत महान है
मातृ मृत्यु दर में कमी लाने की दिशा में प्रगति - 2016-2018 में 130/100,000 जीवित जन्मों के एमएमआर से एमएमआर तक
2018-2020 में 97/100,000- संस्थागत प्रसव और प्रसवपूर्व देखभाल में वृद्धि सुनिश्चित करके और सुधार करके
प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक महिलाओं की पहुंच। हालाँकि, भारत को अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। जबकि हम अपना जश्न मनाते हैं
उपलब्धियाँ, हमें उन चुनौतियों का सामना करना चाहिए जो बनी रहती हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर गर्भावस्था सुरक्षित है, और हर महिला सुरक्षित है
सर्वोत्तम संभव देखभाल का आश्वासन दिया गया है।

यह स्वीकार करते हुए कि भारत अब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, अधिकांश राज्यों ने एक इष्टतम देखना शुरू कर दिया है
अधिक स्थिर जनसंख्या वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कुल प्रजनन दर। लेकिन गर्भावस्था से गुजरना हमेशा आसान नहीं होता है
जोखिम कारकों से भरपूर है। उल्लिखित अंश में संदर्भित अध्ययन से पता चलता है कि पूरे भारत में औसतन 49.1%
गर्भधारण के मामले उच्च जोखिम वाले हैं। जन्म के समय कम अंतर - दो गर्भधारण के बीच 18 महीने से कम - सूची में सबसे ऊपर है
योगदान देने वाले जोखिम कारकों में से 31% की भरपाई होती है, इसके बाद पिछले प्रतिकूल परिणाम 19% होते हैं। ये जोखिम हैं
सीमित या बिना शिक्षा वाली महिलाओं में अनुपातहीन रूप से अधिक। एक स्पष्ट टिप्पणी में, शोधकर्ताओं ने उल्लेख किया
लेख में कहा गया है, "लगभग आधी भारतीय महिलाएं अपनी अगली गर्भावस्था में देरी के लिए गर्भनिरोधक का उपयोग नहीं कर रही थीं"। यह एकदम निरा है
हमारी स्वास्थ्य देखभाल और शैक्षिक प्रणालियों में एक महत्वपूर्ण अंतर की याद दिलाती है: निरंतर, सुसंगत, का कम उपयोग
प्रभावी, आधुनिक गर्भनिरोधक. महिलाओं और उनके सहयोगियों को आधुनिकता के बारे में अधिक जानकारी और उस तक पहुंच की आवश्यकता है
गर्भनिरोधक उत्पाद उन्हें यह चुनने में मदद करते हैं कि उनके शरीर के लिए सबसे अच्छा क्या है।

गर्भावस्था एक गहन शारीरिक अनुभव है। गर्भधारण के बीच दो-तीन साल का अंतर रखने की सलाह दी जाती है
एक महिला को बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार होने से पहले ठीक होने, अपना स्वास्थ्य, शक्ति और पोषण प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय दें
दूसरे बच्चे के लिए और उसकी देखभाल करना। स्वास्थ्य लाभ से परे, जब महिलाएं अपने ऊपर स्वायत्तता और एजेंसी का प्रयोग करती हैं
शरीर और प्रजनन निर्णय, वे सशक्तिकरण के क्षेत्र में कदम रख रहे हैं जिसका प्रभाव परे है
खुद।

· भारतीय परिवार नियोजन कार्यक्रम ने कई वर्षों से प्रभावी रूप से आधुनिक लोगों के लिए विकल्पों की एक श्रृंखला पेश की है
तरीके - और अधिकांश हिस्सों में अपूरित आवश्यकता को कम करने में कई मील के पत्थर तक पहुंच गया है
देश। सार्वजनिक क्षेत्र में, वर्तमान टोकरी में कंडोम, संयुक्त मौखिक गर्भनिरोधक गोलियाँ, आपातकालीन शामिल हैं
गर्भनिरोधक गोलियाँ, अंतर्गर्भाशयी गर्भनिरोधक उपकरण (आईयूसीडी), एक इंजेक्टेबल गर्भनिरोधक (मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन)
एसीटेट या एमपीए) और गर्भनिरोधक गोली सेंटक्रोमैन (छाया)। इसके अतिरिक्त, दो नई विधियाँ - एक सबडर्मल
गर्भनिरोधक प्रत्यारोपण (एचआई) और चमड़े के नीचे इंजेक्टेबल गर्भनिरोधक (डीएमपीए-एससी) - को पेश किया गया है
कुछ राज्यों के सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (हालाँकि ये दोनों विधियाँ अभी निजी क्षेत्र में उपलब्ध नहीं हैं)।
इन्हें लगाना आसान है और ये तीन साल (चमड़े के नीचे के प्रत्यारोपण) और तीन-चार साल तक गर्भधारण को रोक सकते हैं
एक समय में महीने (डीएमपीए-एससी) इस प्रकार उन्हें सुविधाजनक और विवेकपूर्ण विकल्प बनाते हैं। ये सभी विधियां सुरक्षित, उच्च गुणवत्ता वाली और प्रतिवर्ती हैं।

साक्ष्य से पता चलता है कि देश में अभी भी उपयोग में आने वाली सबसे आम आधुनिक विधियाँ महिला नसबंदी (जो) हैं
स्थायी है), और पुरुष कंडोम(जो अक्सर गलत तरीके से उपयोग किए जाते हैं - जिससे उनकी प्रभावशीलता कम हो जाती है - और महिलाएं
हमेशा उनका उपयोग करने का विकल्प नहीं हो सकता है)। जागरूकता और साक्ष्य-आधारित जानकारी प्रोत्साहित करने की कुंजी है
लोग अपने लिए सर्वोत्तम तरीका चुनें। हालाँकि, अंत में जानकारी और समझ की कमी है
उपयोगकर्ताओं और समुदायों के साथ सीमित जुड़ाव का मतलब यह हो सकता है कि लोग सहज और सशक्त महसूस नहीं करते हैं
ये विकल्प चुनें। गलत धारणाएं, नकारात्मक अनुभव, गलत सूचना और वर्जनाएं, अक्सर झिझक को बढ़ावा देती हैं। बेहतर
परामर्श और मजबूत संचार अत्यावश्यक है।

और यहीं पर चिकित्सा प्रदाता आते हैं। सूचना के भरोसेमंद स्रोतों के रूप में, यह चिकित्सा पर निर्भर है
प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे कि लोगों के पास सटीक जानकारी हो जो उन्हें अपने अधिकार का प्रयोग करने में मदद कर सके
चुन लेना। गर्भनिरोधक और परिवार नियोजन एक महिला की स्वतंत्रता, उसकी एजेंसी, उसकी शारीरिक स्वतंत्रता का एक अनिवार्य हिस्सा हैं
स्वायत्तता - उसका सशक्तिकरण। जब हम यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि हमारी महिलाएं सशक्त हैं, तो हम उन्मुक्त हो सकते हैं और पूर्णता का एहसास कर सकते हैं
नारी शक्ति की क्षमता.

(जयदीप टांक के अध्यक्ष हैं फेडरेशन ऑफ प्रसूति एवं स्त्री रोग संबंधी सोसायटी भारत (FOGSI))

Machine Translated by Google

अध्ययन में संतरे के स्वाद के लिए 26 यौगिकों को जिम्मेदार पाया गया है

शोधकर्ताओं ने संतरे के स्वाद के लिए जिम्मेदार प्रमुख यौगिकों की खोज की है। 179 से अधिक जूस के नमूनों का मूल्यांकन करके, शोधकर्ताओं ने संतरे के स्वाद के लिए महत्वपूर्ण 26 यौगिकों की पहचान की, जिनमें सात एस्टर भी शामिल हैं जो इसे मैंडरिन स्वाद से अलग करते हैं। आनुवंशिक विश्लेषणों से पता चला कि इन एस्टर के उत्पादन के लिए पहले से वर्णित अल्कोहल एसाइलट्रांसफेरेज़ जीन जिम्मेदार है, जो रोग प्रतिरोधी, नारंगी जैसे संकरों के स्वाद गुणों की भविष्यवाणी करने के लिए एक संभावित डीएनए मार्कर की ओर इशारा करता है।

Machine Translated by Google

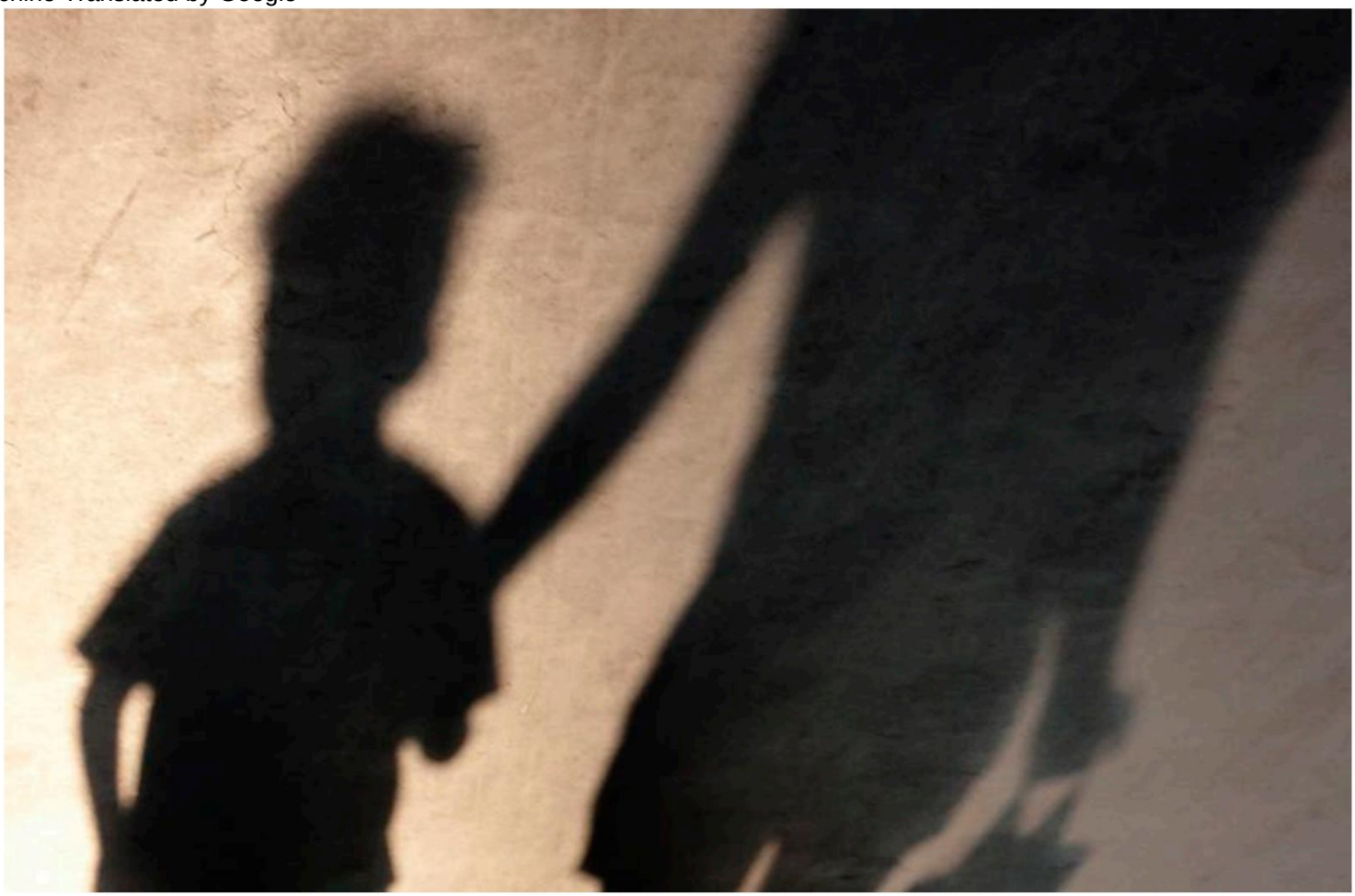

बच्चों में लगातार सूजन से मौतें बढ़ जाती हैं

वैज्ञानिकों ने बताया है कि कैसे कुपोषण के गंभीर मामलों में अस्पताल में भर्ती बच्चों पर, ठीक होने के बाद भी, स्थायी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दक्षिणी अफ्रीका में 437 बच्चों पर किए गए उनके शोध से यह भी संकेत मिलता है कि लंबे समय तक सूजन से परिणामों में सुधार हो सकता है और अस्पताल में भर्ती होने के बाद के महीनों में मृत्यु का खतरा कम हो सकता है। पांच साल से कम उम्र के बच्चों में होने वाली लगभग 45% मौतें कुपोषण से जुड़ी हैं, जिसने संयुक्त राष्ट्र को वर्ष 2030 तक दुनिया भर में कुपोषण को समाप्त करने का लक्ष्य रखने के लिए प्रेरित किया है।

Machine Translated by Google

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हमारे संसाधनों का प्रबंधन

2 में से 1 की बात हो रही है

विज्ञान

डी. बालासुब्रमण्यम

इन दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) शब्द हर जगह छाया हुआ है। जनता इसे मिश्रित दृष्टि से देखने लगी है धारणाएँ एक तरफ, यह एक समस्या-समाधानकर्ता है: एआई ने हृदय की समस्याओं और आंखों की स्थिति की निगरानी करने में मदद की है प्रस्तावित उपचार विकल्प; एआई प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी करता है और नई दवा के अणुओं के विकास में सहायता करता है। वैसे ही, यह चक्रवातों, मानसून की ताकत आदि की भविष्यवाणी करता है। अंधेरे पक्ष में यह डर है कि सोचने वाली मशीनों से नौकरियां खत्म हो सकती हैं 24/7 काम करें और उन्हें दिवाली की छुट्टियों की आवश्यकता नहीं है, और वे आपकी गोपनीयता में हस्तक्षेप कर सकते हैं और आपके डेटा का दुरुपयोग कर सकते हैं। परन्तु कोई नहीं संदेह है कि एआई हमें बड़े पैमाने की समस्याओं का समाधान करने में मदद करेगा जिनके लिए विशाल डेटा के विश्लेषण की आवश्यकता होती है।

जैसे-जैसे भारत का विकास गति पकड़ रहा है, हमें संसाधन सीमाओं की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। हमें आवश्यकता हो सकती है हमारे पास जितना है उससे कहीं अधिक. यह विशेष रूप से पानी के बारे में सच है - हर साल हम देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ देखते हैं दूसरों में सूखा. इंजीनियरों ने इन समस्याओं को कम करने के लिए हमारी नदियों के बीच लिंक बनाने का लंबे समय से सपना देखा है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर बदलावों के प्रभावों पर अनिश्चितताओं ने कई पहलों को रोक दिया है।

Linking rivers

देश के योजनाकारों के लिए, जलवायु परिवर्तन के इस युग में पानी की कमी को कम करना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया है अप्रत्याशित मौसम. क्या परिवर्तन लाने के बारे में पूर्वानुमान लगाने के लिए एआई टूल का उपयोग किया जा सकता है? कम्प्यूटेशनल आईआईटी-आईएसएम, धनबाद और त्रिपुरा और गोवा में एनआईटी के मॉडलर्स ने प्रस्तावित की जांच करते समय ऐसा ही किया है पेन्नार-पालार-कावेरी लिंक नहर।

यह नहर बाढ़ प्रवण महानदी और गोदावरी नदियों को 'घाटे वाली' नदियों से जोड़ने की योजना का हिस्सा है दक्षिण। लिंक नहर आंध्र प्रदेश के नेल्लोर से लेकर जिलों की श्रृंखला में आधा मिलियन हेक्टेयर भूमि की सहायता करेगी तमिलनाडु में कुड्डालोर. ऐसे प्रस्तावों में उद्देश्यों का एक जटिल समूह होता है, जिसे खोजकर मॉडल बनाया जा सकता है अधिकतम लोगों को अधिकतम लाभ।

Fulfilling objectives

बहुउद्देश्यीय मॉडल में, लक्ष्य एक से अधिक उद्देश्यों को इष्टतम ढंग से प्राप्त करना है। उदाहरण के लिए, एक किसान चाह सकता है पानी के न्यूनतम उपयोग से अपनी फसल की अधिकतम उपज प्राप्त करें। वह अपने सिस्टम को उस बिंदु तक बदल देगा जहां वह दूसरे को ख़राब किए बिना एक उद्देश्य में सुधार नहीं किया जा सकता।

आईआईटी-एनआईटी टीम ने एक मॉडल प्रस्तुत किया है जिसका उद्देश्य भूजल को कम किए बिना खेतों से रिटर्न में सुधार करना है या नदियों और जलाशयों में पानी बर्बाद कर रहे हैं (, वी-279, 2023)। उन्होंने **कृषि जल प्रबंधन** उपयोग किया है राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी द्वारा पिछले कुछ वर्षों में (ए) पहले और बाद के जल स्तर पर संग्रह किया गया है इन जिलों के 1.2 लाख कुओं और ट्यूबवेलों में मानसून; (बी) फसल-बुवाई पैटर्न; (सी) प्रचलित न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों को लागत और लाभ। यह एआई-आधारित मॉडलिंग प्रयास अनुकूल परिणाम सुझाता है जुलाई और नवंबर के दो मौसमों में उगाई जाने वाली फसलों की पसंद में कुछ समायोजन के साथ आएगा। अधिक विस्तृत डेटा एकत्र करने से ऐसे एआई-आधारित मॉडलों को अधिक केंद्रित भविष्यवाणियां करने में मदद मिलेगी।

(लेख किसके सहयोग से लिखा गया था? में सुशील चंदानी, जो आणविक मॉडलिंग का काम करते हैं)

Machine Translated by Google

गगनयान भारत के लिए क्या बदलेगा?

What are some of the goals laid down by the Indian Space Research Organisation? Why is a crewed flight technologically ambitious? How many test flights are scheduled before the space mission with a crew takes place?

ऊंचाइयों को छूना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी) में नामित अंतरिक्ष यात्रियों के साथ। पीटीआई - Photo:

VASUDEVAN MUKUNTH

ऐसे स्थापित होगा भारत का आत्म-

विदेशी प्रक्षेपण सेवाओं के साथ महंगे अनुबंधों पर निर्भर रहने के बजाय, मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजने में पर्याप्तता

The story so far:

27 फरवरी को, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन - जिसे गगनयान कहा जाता है - में अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए उम्मीदवारों की अंतिम शॉर्टलिस्ट को सार्वजनिक किया।
यह मानते हुए कि इस वर्ष और अगली दो महत्वपूर्ण परीक्षण उड़ानें सफल हैं, मिशन की पहली चालक दल उड़ान 2025 के लिए निर्धारित है।

What is Gaganyaan?

गगनयान भारतीय प्रक्षेपण यान पर भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को छोटी अवधि के लिए निचली-पृथ्वी की कक्षा में भेजने के इसरो मिशन का नाम है। तकनीकी रूप से, यह एक प्रदर्शन मिशन है: यह मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए आवश्यक विभिन्न तकनीकों का परीक्षण करेगा, जो अंतरिक्ष उड़ान का सबसे जटिल रूप है, और उनके उत्पादन, योग्यता और उपयोग के साथ भारत की परिचितता को प्रदर्शित करेगा। पिछले साल, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो को 2035 तक एक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन बनाने और 2040 तक चंद्रमा पर एक भारतीय को उतारने का "निर्देश" दिया था। जबकि इसके सबसे हालिया मिशनों ने एक विश्वसनीय लॉन्च प्रदाता के रूप में इसरो की प्रतिष्ठा को मजबूत किया है, जो परिष्कृत अंतरग्रहीय मिशनों को उड़ाने में भी सक्षम है। चंद्रयान-3 समेत दो नए लक्ष्य तकनीकी रूप से और भी महत्वाकांक्षी हैं।

इसके अलावा, इसरो भविष्य के चंद्रमा मिशनों के साथ इन्हें निष्पादित करने का प्रयास करेगा। चंद्रयान-3 ने इसरो के चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम के पहले चरण का समापन किया। दूसरा चरण चंद्रमा पर एक रोवर उतारने के लिए जापान के साथ एक संयुक्त मिशन के साथ शुरू होता है और दूसरा चंद्रमा की मिट्टी का नमूना इकट्ठा करने और उसे पृथ्वी पर वापस लाने के लिए है। इन उद्देश्यों के लिए, भारत सरकार ने अंतरिक्ष उड़ान और सेवाओं से संबंधित जिम्मेदारियों को दो नए कार्यालयों में विभाजित कर दिया है जो एक बार पूरी तरह से इसरो के पास थीं। वे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL; अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों का व्यावसायीकरण करने के लिए) और भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe; सभी क्षेत्रों में अंतरिक्ष गतिविधियों को अधिकृत करने के लिए) हैं। इसरो ने गगनयान के लिए एक समन्वय निकाय भी स्थापित किया जिसे मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र (एचएसएफसी) कहा जाता है।

What are the components of Gaganyaan?

गगनयान में एचएसएफसी के अलावा निम्नलिखित घटक शामिल हैं:

प्रक्षेपण यान मार्क-3: एलवीएम-3 प्रक्षेपण यान है। पहले इसे GSLV Mk-III कहा जाता था, यह तीन चरणों वाला रॉकेट है।
पहले चरण में रॉकेट कोर से जुड़े दो ठोस-ईंधन बूस्टर शामिल हैं। दूसरा चरण दो तरल-ईंधन और क्लस्टर विकास 2 इंजन द्वारा संचालित है। तीसरे चरण में क्रमशः ईंधन और ऑक्सीडाइज़र के रूप में तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन के साथ सीई -20 स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन है।

कक्षीय मॉड्यूल: 8.2-टन कक्षीय मॉड्यूल वह वस्तु है जिसे LVM-3 रॉकेट लॉन्च करेगा और निचली-पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करेगा। इसमें क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल शामिल हैं। क्रू मॉड्यूल में एक सप्ताह तक तीन अंतरिक्ष यात्री रह सकते हैं। इसमें कक्षा से उतरने के बाद जमीन पर उतरने की गति को धीमा करने के लिए पैराशूट शामिल हैं; एक पर्यावरण नियंत्रण और जीवन-समर्थन प्रणाली (ईसीएलएसएस; तापमान, सांस लेने के वातावरण, अपशिष्ट निपटान, अग्नि सुरक्षा, आदि को नियंत्रित करने के लिए); और चालक दल से बचने की प्रणाली, जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री रॉकेट की चढ़ाई के दौरान खराबी की स्थिति में भागने के लिए कर सकते हैं। सर्विस मॉड्यूल में रॉकेट से अलग होने के बाद कक्षीय मॉड्यूल की ऊंचाई बढ़ाने और बाद में इसे पृथ्वी की ओर वापस लाने के लिए आवश्यक प्रणोदन प्रणाली शामिल है।

चालक दल: पहले चार अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवारों में से, प्रशांत नायर, अजीत कृष्णन, और अंगद प्रताप ग्रुप कैप्टन हैं और शुभांशु शुक्ला एक विंग कमांडर हैं, सभी भारतीय वायु सेना (आईएएफ) में हैं। जब गगनयान को मंजूरी दी गई, तो IAF ने उम्मीदवारों की एक लंबी सूची तैयार की, जिन्हें IAF के इंस्टीट्यूट ऑफ एयरोस्पेस मेडिसिन में प्रशिक्षित किया गया था। बाद में उम्मीदवारों की एक शॉर्टलिस्ट को उन्नत प्रशिक्षण के लिए रूस भेजा गया। चालक दल के मॉड्यूल में 'व्योममित्रा' नाम का एक गाइनोइड (स्त्री रोबोट) शामिल होगा, जो विकिरण और भारहीनता के प्रभावों को ट्रैक करने, कैप्सूल की स्थिति की निगरानी करने और आसन्न आपात स्थिति की स्थिति में अलार्म बजाने के अलावा कुछ अन्य कार्य करने में सक्षम होने के लिए सेंसर से सुसज्जित होगा। कार्य.

How was the mission put together?

2018 में जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गगनयान को मंजूरी दी, तब तक इसरो को कई अंतर्निहित प्रौद्योगिकियों का एहसास हो गया था।
अनुमोदन के बाद, यह उनमें से कई को मानव-दर देने के लिए आगे बढ़ा, यानी यह सुनिश्चित किया कि उनकी विश्वसनीयता मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए न्यूनतम सीमा को पूरा करती है।

इसने पहले ही 2007 में 'स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट' (एसआरई) और 2014 में 'क्रू-मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री-एंट्री एक्सपेरिमेंट' (सीएआरई) का आयोजन किया था। 2007 में, कक्षा में स्थापित एक उपग्रह 635 किमी की ऊंचाई से नीचे आया था। बंगाल की खाड़ी में गिरने के लिए। 2014 में, मॉड्यूल का एक प्रोटोटाइप LVM-3 रॉकेट पर लॉन्च किया गया था। यह 126 किमी की ऊंचाई पर अलग हुआ, प्रतिगामी प्रणोदकों के साथ 80 किमी तक नीचे उतरा और अंत में पैराशूट के साथ बंगाल की खाड़ी में गिरा। एसआरई और केयर ने मिलकर मॉड्यूल के पृथक्करण तंत्र, हीट शील्ड, ब्रेकिंग सिस्टम, पैराशूट, फ्लोटेशन डिवाइस (पानी में) और पुनर्प्राप्ति प्रक्रियाओं का परीक्षण किया। इसरो ने पिछले साल 21 अक्टूबर को इसी तरह का एक परीक्षण किया था - एक क्रू मॉड्यूल को 'आपातकालीन गर्भपात' कमांड का उपयोग करके बाहर निकलने से पहले एक छोटे रॉकेट पर लॉन्च किया गया था, इसके बाद इसके वंश और पुनर्प्राप्ति का परीक्षण किया गया था।

अक्टूबर 2023 में, इसरो के अध्यक्ष एस. सोमनाथ ने क्रू मॉड्यूल को बताया कि इसे हिंदू के निर्माण की कोई घरेलू क्षमता नहीं थी
"बाहर से" खरीदना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि विदेश से ईसीएलएसएस से संबंधित प्रौद्योगिकियों को प्राप्त करने की इसरो की आशा सफल नहीं हुई, जिससे संगठन के इंजीनियरों को उन्हें आंतरिक रूप से विकसित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब तक इसरो उनकी विश्वसनीयता पर हस्ताक्षर नहीं कर सका, तब तक इंजन और रॉकेट चरणों सहित अन्य प्रमुख घटकों का भी इसी तरह का परीक्षण किया गया। यह परीक्षणों, सिमुलेशन और गुणवत्ता-नियंत्रण अभ्यासों की एक श्रृंखला के माध्यम से हुआ है। उदाहरण के लिए, इसरो ने 21 फरवरी को कहा कि उसने उड़ान के दौरान जैसी स्थितियों में कुल मिलाकर 8,810 सेकंड के लिए चार सीई-20 इंजनों का परीक्षण पूरा कर लिया है।

What will Gaganyaan achieve?

NSIL और IN-SPACe का जन्म अंतरिक्ष क्षेत्र में व्यापक सुधारों के बाद हुआ। वे राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति 2022, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 और दूरसंचार अधिनियम 2023 में शामिल हो गए। 21 फरवरी को, भारत के उभरते अंतरिक्ष स्टार्टअप परिदृश्य को बढ़ावा देते हुए, कैबिनेट ने 49% से 100% स्वचालित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को भी मंजूरी दे दी। अंतरिक्ष सेवाएँ और अंतरिक्ष उड़ान। अंतरिक्ष नीति विशेष रूप से एक सिंहावलोकन प्रदान करती है कि आने वाले दशकों में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का लक्ष्य क्या होगा क्योंकि भारत वैज्ञानिक, वाणिज्यिक और खोजपूर्ण मिशनों का संचालन करते हुए अंतरिक्ष, चंद्रमा और उससे आगे जाने वाले देशों में शामिल हो गया है। यह नई 'अंतरिक्ष दौड़' पृथ्वी पर खींची गई भू-राजनीतिक सीमाओं को बाहरी अंतरिक्ष तक बढ़ाती है। इसका परिणाम अंतरिक्ष और चंद्रमा पर लंबी अवधि के लिए विभिन्न राष्ट्रीयताओं के मानव उपस्थिति पर भारी प्रीमियम है।

इस पृष्ठभूमि में, गगनयान अंतरिक्ष में मनुष्यों को भेजने के मामले में भारत की आत्मनिर्भरता स्थापित करेगा, विदेशी लॉन्च सेवाओं के साथ महंगे अनुबंधों पर निर्भर रहने के बजाय, समय-सीमा को नियंत्रित कर सकता है - और फाइनल में भारत का प्रतिनिधित्व करने के अन्य प्रयासों के साथ कदम मिलाकर सीमांत.

Machine Translated by Google

केंद्र की सीमा योजना के खिलाफ प्रस्ताव

Why have two northeast States opposed the scrapping of the Free Movement Regime with Myanmar?

RAHUL KARMAKAR

मिजोरम और नागालैंड को लगता है कि सीमा पर बाड़ लगाने से उनकी पुश्तैनी जमीन बंट जाएगी और खून के रिश्ते वाले लोग अलग-थलग पड़ जाएंगे; केंद्र का कहना है कि बाड़ लगाने से चरमपंथियों और मादक पदार्थों की सीमा पार आवाजाही पर रोक लगेगी

The story so far:

28 फरवरी को मिजोरम विधानसभा और 1 मार्च को नागालैंड विधानसभा ने 1,643 किलोमीटर लंबी छिद्रपूर्ण भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और फ्री मूवमेंट रिजीम (एफएमआर) समझौते को रद्द करने के केंद्र के फैसले का विरोध करने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया, जो सीमा पार आवाजाही की अनुमति देता है। बिना यात्रा दस्तावेज के 16 किमी.

What led to the resolutions?

20 जनवरी को गुवाहाटी में एक आधिकारिक कार्यक्रम में, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र ने भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और दक्षिण पूर्व में सांस्कृतिक, व्यापार और स्थलीय कनेक्टिविटी के लिए भारत की एक्ट ईस्ट नीति के हिस्से के रूप में 2018 में लागू एफएमआर को खत्म करने का फैसला किया है। एशिया और उससे आगे. केंद्र ने लोगों के अवैध प्रवास, ड्रग्स, हथियारों और गोला-बारूद की तस्करी और चरमपंथियों की सीमा पार आवाजाही को रोकने के लिए एफएमआर को निलंबित करने का निर्णय लिया। यह निर्णय मणिपुर सरकार के दबाव से प्रभावित था - 3 मई, 2023 को मेइतेई और कुकी-ज़ो लोगों के बीच जातीय हिंसा शुरू होने के बाद - म्यांमार के नागरिकों को राज्य में अवैध रूप से बसने से रोकने के लिए सीमा पर बाड़ लगाने की मांग की गई थी। अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर ने केंद्र के फैसले का स्वागत किया, लेकिन म्यांमार की सीमा से लगे अन्य दो राज्यों मिजोरम और नागालैंड ने सीमा पर "ब्रिटिश शासकों द्वारा थोपी गई" जातीय संरचना और उनके सदियों पुराने सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यापार संबंधों के कारण इसका विरोध किया।

Why is the India-Myanmar border in focus?

भारत का म्यांमार के साथ 1948 से लगातार राजनयिक संबंध रहा है, जब म्यांमार को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली थी। 1960, 1980 और फरवरी 2021 के बाद म्यांमार में सैन्य तख्तापलट और लोकतंत्र समर्थक आंदोलनों के बाद भारत के सीमावर्ती जिलों में बड़ी संख्या में शरणार्थी आए। म्यांमार में बढ़ते चीनी प्रभाव ने नई दिल्ली को यांगून (बाद में न्यापीडॉ) के साथ मधुर संबंध स्थापित करने के लिए मजबूर किया, लेकिन कुछ मुद्दे रह गया. भारत की सीमा से लगे म्यांमार के क्षेत्रों को जातीय मिलिशिया और अराकान आर्मी, चिन नेशनल फ्रंट और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) जैसे चरमपंथी समूहों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिनमें से कुछ ने यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट जैसे पूर्वोत्तर-आधारित संगठनों को आश्रय दिया है। असोम का. इन संगठनों ने भारत में हिट-एंड-रन ऑपरेशन को अंजाम दिया है। हालाँकि म्यांमार सीमा की सुरक्षा अर्धसैनिक बल असम राइफल्स द्वारा की जाती है, लेकिन कहा जाता है कि इलाके और बाड़ की कमी के कारण चरमपंथियों की आवाजाही और ड्रग्स, हथियारों और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी को रोकना मुश्किल हो गया है।

What do the resolutions say?

भारत का वर्तमान उत्तर-पूर्व का अधिकांश भाग अस्थायी रूप से बर्मा के कब्जे में था, जब तक कि 1800 के दशक में अंग्रेजों ने उन्हें बाहर नहीं कर दिया। विजेताओं और पराजितों ने 1826 में यांडाबू की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिससे भारत और बर्मा के बीच सीमा का वर्तमान संरेखण हुआ, जिसे बाद में म्यांमार का नाम दिया गया। सीमा ने समान जातीयता और संस्कृति के लोगों को - विशेष रूप से नागालैंड और मणिपुर के नागाओं और मणिपुर और मिजोरम के कुकी-चिन-मिज़ो समुदायों को उनकी सहमति के बिना विभाजित कर दिया। मिज़ो-चीन के लोगों के एक साथ रहने के अधिकार पर जोर देते हुए मिजोरम के गृह मंत्री के. सपडांगा ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि बाड़ लगाने से उनकी पुश्तैनी जमीन बंट जाएगी और खून के रिश्ते वाले लोग अलग हो जाएंगे। नागालैंड के उपमुख्यमंत्री वाई पैटन ने राज्य विधानसभा में प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि केंद्र के इस कदम से अंतरराष्ट्रीय सीमा के दोनों ओर रहने वाले नागा लोगों के सदियों पुराने संबंध बाधित होंगे। श्री।

सपडांगा ज़ोरम पीपुल्स मूवमेंट से संबंधित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह पार्टी भाजपा द्वारा समर्थित है। श्री पैटन भाजपा के एक प्रमुख नेता हैं, जो नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन में एक छोटा सा भागीदार है।

What impact will the resolutions have?

मार्च 2021 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य विधानसभाओं द्वारा नागरिकता (संशोधन) अधिनियम जैसे केंद्रीय कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव अपनाने में कोई नुकसान नहीं है। इसमें कहा गया है कि ऐसे प्रस्ताव विधानसभा के बहुमत सदस्यों की केवल "राय" हैं और इनमें कानून की शक्ति नहीं है। पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों ने पिछले दशकों में कई प्रस्ताव अपनाए हैं, लेकिन लोगों की भावनाओं को प्रतिबिंबित करने के अलावा इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, हालांकि "शुष्क" मिज़ोरम में मिज़ोस का एक वर्ग मुख्य रूप से भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के खिलाफ नहीं है। दवाओं की आमद. मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने पहले कहा था कि उनकी सरकार के पास केंद्र को सीमा पर बाड़ लगाने और एफएमआर को खत्म करने से रोकने का अधिकार नहीं है। लेकिन सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि प्रतिकूल इलाका, रसद और कनेक्टिविटी के मुद्दे और लोगों के बीच समानता के कारण सीमा पर बाड़ लगाना मुश्किल हो जाएगा।

Machine Translated by Google

चुने गए चार

Gaganyaan astronauts Group Captains Prasanth Balakrishnan Nair, Ajit Krishnan and Angad Pratap, and Wing Commander Shubanshu Shukla, all with the Indian Air Force, have been chosen as the astronaut-candidates for the first human spaceflight mission of the Indian Space Research Organisation

From left: Wing Commander Shubanshu Shukla and Group Captains Prasanth Balakrishnan Nair, Ajit Krishnan and Angad Pratap

VASUDEVAN MUKUNTH

The gist

- पहले गगनयान मिशन की वर्तमान योजना चालक दल में दो अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की है
400 किमी की ऊंचाई तक अधिकतम एक सप्ताह तक मॉड्यूल
- इस संबंध में, दो उम्मीदवार उड़ान भरेंगे और दो स्टैंड-बाय पर रहेंगे
- गगनयान की पहली उड़ान से पहले चार में से एक को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजे जाने की भी उम्मीद है

27 फरवरी को केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की आधिकारिक यात्रा के दौरान एक समारोह में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन, उर्फ गगनयान के लिए चार अंतरिक्ष यात्री-उम्मीदवारों के नामों का खुलासा किया। संगठन (इसरो)। वे ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, और अंगद प्रताप, और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला हैं - सभी भारतीय वायु सेना के साथ।

गगनयान का उद्देश्य इसरो के लिए भारतीय प्रक्षेपण यान के साथ कम-पृथ्वी की कक्षा में मानव अंतरिक्ष उड़ान का प्रदर्शन करना है। संगठन की टीमें वर्तमान में मिशन के विभिन्न घटकों को मानव-रेटिंग के दौरान अपनी गति से लगा रही हैं - यानी यह सुनिश्चित करना कि उनकी विफलता दर विशिष्ट सीमा से कम है, जिससे उन्हें मनुष्यों के लिए अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए पर्याप्त सुरक्षित बनाया जा सके। गगनयान में दो महत्वपूर्ण मानव रहित परीक्षण उड़ानें आने वाली हैं। यदि वे सफल होते हैं, तो पहली चालक दल वाली उड़ान (अब तक) 2025 के लिए निर्धारित है।

The four candidates

ग्रुप कैप्टन नायर केरल के रहने वाले हैं। उनका जन्म 26 अगस्त 1978 को हुआ था। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, श्री नायर ने एनएसएस इंजीनियरिंग कॉलेज, पलक्कड़ में पढ़ाई की और फिर महाराष्ट्र के खड़कवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में दाखिला लिया।

1997 में एनडीए से स्नातक होने के बाद, उन्हें 1998 में वायु सेना द्वारा लड़ाकू पायलट के रूप में नियुक्त किया गया था। वह एक उड़ान प्रशिक्षक बन गए और बाद में एक परीक्षण पायलट बन गए - पायलटों का एक वर्ग जिनसे नए और/या संशोधित विमान उड़ाने, नई उड़ान तकनीकों का परीक्षण करने और सुरक्षा मापदंडों का मूल्यांकन करने की उम्मीद की जाती है। श्री नायर की शिक्षा से परिचित लोगों के अनुसार, उन्होंने कथित तौर पर शिक्षाविदों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वायु सेना अकादमी में, उन्हें 'स्वोर्ड ऑफ़ ऑनर' प्राप्त हुआ, जो कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले कैडेट के लिए आरक्षित सम्मान था। कहा जाता है कि एक परीक्षण पायलट के रूप में भी उन्होंने 3,000 घंटे से अधिक की उड़ान भरी और Su-30 विमान के एक स्क्वाड्रन की कमान संभाली, साथ ही अन्य विमान भी उड़ाने में सक्षम थे।
श्री नायर और मलयालम फिल्म अभिनेता लीना कुमार की शादी इस साल जनवरी में एक निजी समारोह में हुई थी।

गगनयान के लिए उम्मीदवारों की अंतिम शॉर्टलिस्ट में अजीत कृष्णन का चयन भी इसी प्रक्षेपवक्र का अनुसरण करता है। श्री कृष्णन का जन्म 19 अप्रैल 1982 को हुआ था और वह चेन्नई के रहने वाले हैं। उन्होंने 2002 में एनडीए से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, वायु सेना अकादमी में 'स्वोर्ड ऑफ ऑनर' प्राप्त किया, और अंततः 2003 में वायु सेना द्वारा कमीशन किया गया। वह एक परीक्षण पायलट भी हैं, जिन्होंने 2,900 घंटे की उड़ान भरी है, और हैं सुखोई, मिग, जगुआर, हॉक, डोर्नियर और एंटोनोव एएन-32 विमान उड़ाने में सक्षम।

श्री कृष्णन के एनडीए से पास होने के एक साल बाद, अंगद प्रताप (जन्म 17 जुलाई, 1982, प्रयागराज) ने भी यही अनुसरण किया। उन्हें 2004 में वायु सेना द्वारा कमीशन दिया गया था और वह एक परीक्षण पायलट भी बने, उन्होंने लगभग 2,000 घंटे की उड़ान और कई विमान उड़ाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया।

शुभांशु शुक्ला (जन्म 10 अक्टूबर 1985, लखनऊ में) ने 2005 में एनडीए में अपना प्रशिक्षण पूरा किया और 2006 में एक लड़ाकू पायलट के रूप में वायु सेना में शामिल हो गए, और श्री प्रताप के समान उड़ान अनुभव के साथ एक परीक्षण पायलट बन गए। .

वायु सेना के प्रति अपने प्रशिक्षण और जिम्मेदारियों के कारण, परीक्षण पायलट मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रयासों के लिए पसंदीदा अंतरिक्ष यात्री रहे हैं। राकेश शर्मा, जो 1984 में सोवियत संघ के सोयुज टी-11 मिशन को लॉन्च करने के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय नागरिक बने, एक परीक्षण पायलट भी थे।

एनडीए का प्रशिक्षण कार्यक्रम तीन वर्षों में छह कार्यकाल तक चलता है। वायु सेना द्वारा कमीशन प्राप्त करने के इच्छुक कैडेट पांचवें और छठे कार्यकाल में वायु सेना प्रशिक्षण दल (एएफटीटी) के साथ प्रशिक्षण लेते हैं। उनके पाठ्यक्रम में ज़मीनी और उड़ान प्रशिक्षण, विमानन-संबंधी गतिविधियाँ और वायु सेना में उनके पेशेवर प्रशिक्षण से संबंधित विषय शामिल हैं।

एयर मार्शल भूषण गोखले (सेवानिवृत्त) को एएफटीटी को देश में "सैन्य विमानन का उद्गम स्थल" बताते हुए उद्धृत किया गया है। इसकी स्थापना 1956 में स्क्वाड्रन लीडर डगलस जॉर्ज किंग-ली के साथ इसके पहले प्रभारी अधिकारी के रूप में की गई थी।

Astronaut training

2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मिशन को मंजूरी दिए जाने के तुरंत बाद गगनयान के लिए उम्मीदवारों के चयन और प्रशिक्षण पर काम शुरू हुआ। इन गतिविधियों ने दो देशों में कम से कम तीन सुविधाओं को फैलाया है: भारतीय वायु सेना का इंस्टीट्यूट ऑफ एयरोस्पेस मेडिसिन (आईएएम), बेंगलुरु; रूस में गगारिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर (जीसीटीसी); और अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण सुविधा भी बेंगलुरु में है।

सोवियत संघ ने 1960 में अपनी अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण सुविधा स्थापित की और 1968 में इसका नाम दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री और सोवियत संघ के पहले अंतरिक्ष यात्री के नाम पर रखा। सोवियत संघ के विभाजन के बाद, रूस ने 1995 में अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण के राज्य वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना की और इसका नाम भी यूरी गगारिन के नाम पर रखा। इसे रक्षा मंत्रालय की विमानन शाखा और राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रशासित किया गया था। 1960 और 1996 के बीच, केंद्र ने अपने स्वयं के दल के अलावा 17 देशों के 24 अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित किया।

चारों उम्मीदवारों ने जीसीटीसी में 13 महीने तक प्रशिक्षण लिया। इसमें अंतरिक्ष यान नियंत्रण, अतिरिक्त-वाहन गतिविधियों (जैसे स्पेसवॉक), तटस्थ उछाल, माइक्रोग्रैविटी, उच्च-गुरुत्वाकर्षण प्रशिक्षण (प्रक्षेपण के लिए) और अस्तित्व (उदाहरण के लिए, यदि गगनयान क्रू कैप्सूल कहीं और उतरता है) का अनुकरण करने के लिए सुविधाएं शामिल हैं। योजना के अनुसार बंगाल की खाड़ी की तुलना में)।

जीसीटीसी में उम्मीदवारों के 13 महीने के कार्यक्रम के बाद बेंगलुरु में अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण सुविधा में आगे की गतिविधि की गई, जिसे इसरो ने 2022 में गगनयान के लिए चालू किया था। इस 'अस्थायी' सेटअप में तीन सिम्युलेटर शामिल हैं। भविष्य के मिशनों के लिए उसी राज्य में चल्लकेरे साइंस सिटी में एक बड़ा, अधिक स्थायी प्रतिष्ठान स्थापित किया जा रहा है। इसरो के अनुसार, उम्मीदवारों के पास सिद्धांत कक्षाएं भी थीं।

Four powers

जबकि क्रू मॉड्यूल तीन अंतरिक्ष यात्रियों की मेजबानी कर सकता है, इसरो के अध्यक्ष एस. सोमनाथ ने पहले गगनयान मिशन पर केवल एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने से इनकार नहीं किया है - साथ ही मानसिक फिटनेस के महत्व पर भी जोर दिया है।

पहले गगनयान मिशन की वर्तमान योजना क्रू मॉड्यूल पर दो अंतरिक्ष यात्रियों को अधिकतम एक सप्ताह के लिए 400 किमी की ऊंचाई पर भेजने की है। इस संबंध में, दो उम्मीदवार उड़ान भरेंगे और दो स्टैंड-बाय पर रहेंगे। गगनयान की पहली उड़ान से पहले चार में से एक को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजे जाने की भी उम्मीद है।

प्रधान मंत्री मोदी ने चारों पायलटों में से प्रत्येक को "शक्ति" या शक्ति के रूप में संदर्भित किया। गगनयान के लिए चुने जाने से पहले उनकी जिम्मेदारियाँ, फिटनेस परीक्षण और प्रशिक्षण व्यवस्था इस गुण की पुष्टि करती हैं। फिर भी, जैसा कि अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के कई मिशन प्रमाणित करेंगे, अंतरिक्ष यात्रियों और मशीनों की ऐसी कठोर योग्यता - मानव अंतरिक्ष उड़ान की अनिश्चितताओं के लिए अधिक बैंडविड्थ को खुला छोड़ना है।

Machine Translated by Google

'Google के ऐप को डीलिस्ट करने की अनुमति नहीं दी जा सकती'

IT Minister Vaishnaw emphasises Google's delisting of certain apps from Play Store over in-app payment commissions is not acceptable; tells Press Trust of India government will meet company's representatives on Monday; Info Edge says some of its apps restored on complying with the norms

THE HINDU BUREAU
नई दिल्ली

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को बताया कि Google द्वारा कंपनी के एंड्रॉइड प्ले स्टोर से कुछ भारतीय ऐप्स को हटाने की "अनुमति नहीं दी जा सकती" और कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ एक सरकारी बैठक सोमवार को होनी थी।

भारत मैट्रिमोनी, कुकू एफएम और नौकरी जैसे वैवाहिक, स्ट्रीमिंग और नौकरी खोज ऐप्स को Google के एंड्रॉइड ऐप स्टोर से हटा दिया गया था, क्योंकि उन्होंने प्लेटफ़ॉर्म शुल्क का विरोध किया था, जिसके लिए Google उन्हें इन-ऐप खरीदारी पर भुगतान करने के लिए कहता है।

Google के प्रवक्ता ने टिप्पणी के लिए ईमेल से भेजे गए अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया।

'Policy very clear'

श्री वैष्णव ने पीटीआई-भाषा से कहा, "भारत बहुत स्पष्ट है, हमारी नीति बहुत स्पष्ट है... हमारे स्टार्ट-अप को वह सुरक्षा मिलेगी जिसकी उन्हें आवश्यकता है।"

कुछ बड़े ऐप डेवलपर्स द्वारा डिजिटल सामान के लिए उपयोगकर्ताओं द्वारा किए गए भुगतान पर 11-30% कमीशन वसूलने के लिए Google के खिलाफ छेड़ी गई लंबी लड़ाई के बाद शुक्रवार को ऐप्स को हटा दिया गया। जबकि कैब की सवारी या ई-कॉमर्स डिलीवरी जैसे भौतिक उत्पाद खरीद पर यह शुल्क नहीं लगता है, डिजिटल सदस्यता और खरीदारी पर यह शुल्क लगता है। कुछ भारतीय ऐप डिजिटल वस्तुओं के लिए इस तरह के प्रत्यक्ष भुगतान के आधार पर व्यवसाय बनाने में सक्षम हैं, लेकिन वैवाहिक और स्ट्रीमिंग ऐप उन प्रमुख ऐप्स में से हैं जिनके लिए ऐसा राजस्व पर्याप्त है।

सुप्रीम कोर्ट ने इन ऐप्स को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया, जो पिछले साल मद्रास उच्च न्यायालय में Google की फीस के खिलाफ अपना मामला हार गए थे। इसके बाद, Google ने बुधवार को घोषणा की कि वह अब सुनवाई के समापन का इंतजार करके इन ऐप्स को छूट नहीं देगा, और उन्हें डीलिस्ट करने के लिए आगे बढ़ा। टेस्टबुक, एक परीक्षा तैयारी सेवा, और स्ट्रीमिंग सेवा डिज़नी + हॉटस्टार, को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की गई है क्योंकि वे सुप्रीम कोर्ट के मामले में देर से शामिल हुए थे, और उनके ऐप्स को कभी भी असूचीबद्ध नहीं किया गया था।

Naukri restored

कंपनी के सीईओ संजीव बिखचंदानी ने एक्स पर कहा, इन्फो एज (इंडिया) के कुछ ऐप्स, जैसे कि नौकरी और रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म 99एकड़, को Google की भुगतान आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए ऐप्स को अपडेट करने के बाद बहाल कर दिया गया था।

Machine Translated by Google

जंगल में अशांति

Tribal communities, who have relied on resources from the hills around Theni in Tamil Nadu, face challenges after the enforcement of the Forest Act; education could help them stay connected to their roots

जागरूकता पैदा करना: पेरियाकुलम में एक छात्रावास वार्डन, विजयराज, थेनी और डिंडीगुल जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए शिक्षा और कैरियर के अवसरों की पहचान करने के लिए स्वयंसेवक हैं।

पलानी पहाड़ियों से उत्पन्न, पलियार जनजाति जंगलों और वन्य जीवन में अपनी व्यापक विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध है। उनके प्राथमिक व्यवसायों में जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करना, खेती करना, कंदों की खेती करना और मधुमक्खी पालन करना शामिल है। वर्षों से, उनका अस्तित्व पहाड़ियों के भीतर संसाधनों पर निर्भर रहा है।

वन अधिनियम के कार्यान्वयन ने कई स्वदेशी लोगों को मैदानी इलाकों में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर कर दिया है, जहां वे सरकारी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर हैं। वेलप्पर कोविल के लोगों का मामला भी ऐसा ही एक है। 125 एकड़ उपजाऊ भूमि जो कभी कारा पाराई जनजाति की थी, वन विभाग को दे दी गई है, जिसके परिणामस्वरूप भूमि से उनका संबंध और उनकी आजीविका धीरे-धीरे समाप्त हो गई है। इसके अलावा, वे अपनी सांस्कृतिक विरासत को खोने की कगार पर खड़े हैं, क्योंकि वे जंगल के बारे में अपना ज्ञान अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में सक्षम नहीं हैं। समुदाय के युवा सदस्य खुद को बाहरी दुनिया के साथ तालमेल बिठाने और अपनी परंपराओं को संरक्षित करने की चुनौती से जूझते हुए पाते हैं।

यहीं पर उच्च शिक्षा मदद कर सकती है, क्योंकि छात्र अपना रास्ता चुनने में अधिक सशक्त महसूस करेंगे।
पेरियाकुलम में सरकारी आदि द्रविड़ कल्याण लड़कों के छात्रावास में एक छात्रावास वार्डन, विजयराज, पिछले चार वर्षों से थेनी और डिंडीगुल जिलों के क्षेत्रों में आदिवासी छात्रों की शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। उनके स्वैच्छिक कार्यों में आदिवासी गांवों का लगातार दौरा करना, माता-पिता से जुड़ना और सरकारी पहलों, मुफ्त शैक्षिक संसाधनों और छात्रवृत्ति के अवसरों के बारे में जानकारी प्रदान करना शामिल है।

अपने छात्रों को दो समूहों में वर्गीकृत करते हुए, श्री विजयराजा स्कूल-उम्र छोड़ने वाले छात्रों के साथ काम करते हैं जो पुन: आवेदन के लिए पात्र रहते हैं और जो स्कूल की उम्र पार कर चुके हैं लेकिन अभी भी ट्यूटोरियल परीक्षा के लिए पात्र हैं।

वर्तमान में, वह 2024 में तमिलनाडु लोक सेवा आयोग (टीएनपीएससी) समूह 4 परीक्षा के लिए कोचिंग कक्षाओं में दसवीं कक्षा पूरी करने वाले छात्रों को नामांकित करने के मिशन पर हैं। यह परीक्षा वन विभाग में विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित 288 पदों की पेशकश करती है। ऐसे अवसरों से छात्रों को अपनी जड़ों से जुड़े रहने में मदद मिलेगी।